

# न्यूज टुडे

## प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हुए

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) ने भारत में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में PMKVY की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बारे में

- वर्तमान में, यह योजना अपने चौथे चरण (PMKVY-4.0) में है। इसे दो अन्य घटकों के साथ स्किल इंडिया कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना का एक प्रमुख घटक बनाया गया है। PMKVY के दो अन्य घटक निम्नलिखित हैं—
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षता संवर्धन योजना (PM-NAPS): इस योजना के तहत सरकार प्रशिक्षकों को स्टाइपेंड देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना: इसके तहत 15-45 आयु वर्ग के निरक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों (12वीं कक्षा तक) को व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जाता है।
- PMKVY के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रशिक्षण:
  - शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (STT): नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप पाठ्यक्रम और ऑन-जॉब ट्रेनिंग।
  - पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL): मौजूदा कौशल का उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन।
  - विशेष परियोजनाएं: हाथिए पर मौजूद समूहों, दुर्गम क्षेत्रों और विशिष्ट या भविष्य की नौकरी के लिए अनुकूलित कौशल प्रशिक्षण।

PMKVY की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार: वर्ष 2015 से अब तक 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- लक्षित कौशल विकास: हाथिए पर मौजूद समूहों के लिए लक्षित कौशल विकास के तहत लिपुला में 2,500 ब्रू जनजाति के अभ्यर्थियों; असम और मणिपुर की जेलों के कैदियों; तथा 18 राज्यों में PANKH परियोजना के अंतर्गत 70% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- सामाजिक समानता और समावेशन: 45% महिला भागीदारी और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का उल्लेखनीय समावेशन किया गया है।
- भविष्य के लिए तैयार कार्यबल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
- पारंपरिक शिल्पों का प्रोत्साहन: नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के कारीगरों व बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

## PMKVY 4.0 के डिजाइन सिद्धांत



उद्योग से जुड़ाव और  
ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण



प्रशिक्षण इकोसिस्टम  
का डिजिटलीकरण



उद्यमिता पर  
ध्यान



परीक्षकों और प्रशिक्षकों के  
राष्ट्रीय पूल का निर्माण



नई पीढ़ी के कौशल  
पर ध्यान देना

## नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भारत के व्यापार पर अमेरिकी प्रशुल्क (टैरिफ) के प्रभाव का विश्लेषण किया गया

यह रिपोर्ट भारत पर अमेरिकी प्रशुल्क के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुझाव भी देती है।

भारत पर वर्तमान अमेरिकी प्रशुल्क व्यवस्था का प्रभाव

- बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि: भारत उन उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अच्छी स्थिति में है, जिनका वह वर्तमान में अमेरिका को निर्यात करता है, तथा यह वृद्धि उसके कुल निर्यात मूल्य के 61% के बराबर होगी।
- प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: भारत को प्रमुख क्षेत्रों, जैसे- परमाणु रिएक्टर, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, विद्युत उपकरण, वाहन आदि में चीन, मैक्सिको और कनाडा पर प्रशुल्क संबंधी बढ़त मिलेगी।
- हानि: औसत प्रशुल्क नुकसान केवल 1% है, जहां भारत को कुछ अधिक प्रशुल्क का सामना करना पड़ेगा।
- अवसर: उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों (जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु रिएक्टर आदि) और श्रम-प्रधान वस्तुओं (जैसे- परिधान, वस्त्र) में।

अपनाये जाने वाले नीतिगत उपाय

- पण्य (Merchandise) व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
  - निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: श्रम-प्रधान क्षेत्रों को उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना में शामिल करना, क्रॉस-सब्सिडी घटाकर विद्युत प्रशुल्क को तार्किक बनाना आदि।
  - व्यवसाय करने में सुगमता और बाजार तक पहुंच: अधिकृत आर्थिक परिचालक (AEO) कार्यक्रम को बेहतर बनाना, निर्यात संवर्धन मिशन के तहत लक्षित योजनाएं शुरू करना आदि।
  - व्यापार साझेदारों और समझौतों में विविधता लाना: बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनना तथा भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और जन विश्वास 2.0 जैसी पहलों को आगे बढ़ाना।
- सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
  - भारत-यूनाइटेड किंगडम समझौते के मॉडल पर आधारित सेवा-केंद्रित FTA पर वार्ता करना।
  - व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करने के लिए पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs) को व्यापक बनाना।
  - लाइसेंसिंग और विनियामक अनुपालन को सरल बनाना, जैसे सेवा निर्यात में असंगत डेटा अनुपालन एवं बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों को हल करना।
  - कौशल उन्नयन और तकनीक (जैसे- डिजिटल हेल्थ, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडु-टेक) में निवेश करके नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना।



## वित्त मंत्री ने भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की स्थापना दर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया

वित्त मंत्री ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की स्थापना को बढ़ावा देने और अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए उद्योग एवं सरकार से मिलकर काम करने का आग्रह किया है।

वर्ष 2024 में, भारत में हर सप्ताह औसतन 1 नया GCC स्थापित हुआ था।

GCC क्या है

GCC को ग्लोबल इन-हाउस सेंटर या कैप्टिव (GIC) भी कहा जाता है।

ये वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र होते हैं, जो अपनी मूल कंपनी को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे- IT सेवाएं, अनुसंधान और विकास (R&D) सेवाएं, ग्राहक सहायता इत्यादि।

ये केंद्र इन कंपनियों के आंतरिक ढांचे का हिस्सा होते हैं।

भारत में GCC वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक:

- कम लागत में सेवाएं मिलना;
- डिजिटल और नीतिगत तैयारी (स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम);
- कुशल और सस्ता कार्यबल (अंग्रेजी जानने वाले युवा);
- बड़ा उपभोक्ता बाजार आदि।

भारत में GCC के विकास में चुनौतियां

- टियर-II और टियर-III शहरों में कुशल कार्यबल की सीमित उपलब्धता;
- अवसंरचना की कमी (भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी);
- जटिल विनियामक संरचनाएं;
- साइबर सुरक्षा खतरे आदि।

आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप

- नई तकनीकों को अपनाना: जैसे- AI, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि।
- भू-राजनीतिक जटिलताओं से निपटना: जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्यों और परिणामी विनियामक अनिश्चितता से निपटने के लिए अति सक्रिय गवर्नेंस मॉडल अपनाना चाहिए।
- कार्यबल रणनीतियों को पुनर्परिभाषित करना: इसमें प्रतिभा का कौशल विकास करना, नए कौशल सिखाना और हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाना आदि शामिल हैं।
- संधारणीयता: GCC को पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

भारत में GCCs की वर्तमान स्थिति

- वैश्विक उपस्थिति: भारत में 1,800 से अधिक GCCs हैं, जो दुनिया भर के कुल GCCs का लगभग 50% हैं।
- आर्थिक योगदान: GCCs का प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन (GVA) 68 बिलियन डॉलर है। 2030 तक इसके 150-200 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।
- रोजगार के आंकड़े: वर्तमान में लगभग 2.16 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2030 तक इसके 2.5-2.8 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- संवृद्धि दर: पिछले 5 वर्षों में भारत में GCC सेक्टर हर साल औसतन 11% की दर (CAGR) से बढ़ा है। भारत की कुल GDP में GCC सेक्टर का योगदान 1.6% है।

## भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें 50.08% विद्युत का उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से किया गया है।

भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य से पांच साल पहले ही 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत क्षमता में वृद्धि को संभव करने वाली प्रमुख पहलें

- प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना: इसके तहत लगभग 7 लाख सोलर रूफटॉप की स्थापना की जा चुकी है।
- पीएम-कुसुम/ PM-KUSUM: इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कृषि हेतु ऊर्जा सुरक्षा संभव हुई है।
- विनिर्माण का विस्तार: उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से घरेलू स्तर पर सोलर फोटोवोल्टिक और विंड टरबाइन के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

बेहतर होती ट्रांसमिशन अवसंरचना: नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों से बिजली को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणालियों में काफी निवेश किया गया है।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022: ये उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।

वायुबिलिटी गैप फंडिंग (VGF): अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए VGF योजना शुरू की गई है।

इस उपलब्धि का महत्व

- वैश्विक स्तर पर अग्रणी: भारत ने सिद्ध कर दिया है कि विकासशील देश आर्थिक संवृद्धि से समझौता किए बिना स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
- आयात पर निर्भरता में कमी: इससे ऊर्जा के मामले में संप्रभुता में वृद्धि होती है तथा वैश्विक स्तर पर ईंधन के मूल्य में अस्थिरता के प्रति सुभेद्यता में भी कमी आती है।
- ऊर्जा के स्रोतों में विविधता: विविध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एक मजबूत और सक्षम एनर्जी मिक्स संभव होता है।
- रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास: इससे नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में बढ़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है।



क्षेत्र



क्षमता (गीगावाट में)



प्रतिशत

तापीय

242.04 गीगावाट

(49.92%)

परमाणु

8.78 गीगावाट

(1.81%)

बड़ी जलविद्युत

49.38 गीगावाट

(10.19%)

नवीकरणीय ऊर्जा

184.62 गीगावाट

(38.08%)

कुल

484.82 गीगावाट

(100%)

## सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर घृणा कम करने के लिए नागरिकों के बीच भाईचारे पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के दौरान नागरिकों से आत्म-संयम और नियंत्रण बरतने पर जोर दिया है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

- अपनी राय रखना एक अलग बात है, लेकिन उसे किसी खास तरीके से कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और कानून प्रवर्तन पर बोझ बढ़ता है।
- नागरिकों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण न रख पाने की स्थिति में राज्य को ऐसी दुर्भावना वाली प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसे राज्य के खिलाफ (वर्टिकल एप्लिकेशन) तथा अन्य नागरिकों के खिलाफ (होरिजेंटल एप्लिकेशन) भी लागू किया जा सकता है।
- कौशल किशोर केस (2023) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों के होरिजेंटल एप्लिकेशन को मान्यता दी गई थी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सोशल मीडिया का प्रभाव

- सकारात्मक प्रभाव**
  - अपनी बात को रखना: यह हाशिए पर रहने वाले और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को अपनी बात कहने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
  - सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को मजबूत करना: यह नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।
  - जवाबदेही और पारदर्शिता: नागरिक और मीडिया इसका उपयोग सरकारी व्यवस्था को जवाबदेह ठहराने एवं लोक महत्त्व के मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं।
- नकारात्मक प्रभाव**
  - गलत सूचना और फैक न्यूज: इससे दहशत, दंगे, मानहानि हो सकती है।
  - अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार: ऑनलाइन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार व ट्रोलिंग व्यक्तियों को सामाजिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं।
  - एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह: इसमें एल्गोरिदम द्वारा विविध विचारों को कम दिखाना और कुछ खास प्रकार के कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देना शामिल है।



## अन्य सुर्खियां



### टैलिसमैन सेबर अभ्यास (Exercise Talisman Sabre)

ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास “टैलिसमैन सेबर 2025” सिडनी में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ।

‘टैलिसमैन सेबर अभ्यास’ के बारे में

- इसमें 19 देश और 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में आयोजित किया जाता है।
- मुख्य भागीदार: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम आदि।
- पर्यवेक्षक राष्ट्र: मलेशिया और वियतनाम।
- इस अभ्यास में लाइव-फायर अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग गतिविधियां, एम्फीबियस लैंडिंग, थल सेना की चतुराई तथा हवाई युद्ध और सामुद्रिक क्षेत्र में संचालन शामिल हैं।



### नकली सामान

जर्मन ब्रांड बिरकेनस्टॉक (Birkenstock) ने नकली सैंडल बेचने वाले दिल्ली और आगरा के निर्माताओं और व्यापारियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा (Civil suit) दायर किया।

भारत में ‘नकली सामान’ का बाजार

- OECD ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में नकली वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत को एक प्रमुख स्रोत देश के रूप में वर्णन किया था।
- 2022 की CRISIL रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिटेल बाजार में लगभग 25–30% नकली वस्तुएं होती हैं।
- भारतीय कानून के तहत, कोई ब्रांड अपने उत्पादों को ट्रेडमार्क्स एक्ट, 1999 और डिज़ाइन एक्ट, 2000 के जरिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इन कानूनों से ब्रांड को कानूनी कार्रवाई करने, अदालत से राहत पाने और नकली माल जब्त करवाने का अधिकार मिलता है।



### उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में खुदरा (रिटेल) मुद्रास्फीति दर कम होकर 2.10% के स्तर पर आ गई। यह पिछले 6 वर्षों के सबसे कम है।

- CSO केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बारे में

- यह उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में निर्धारित समय में होने वाले परिवर्तनों को मापता है जिन्हें एक परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदता है।
- कार्य/उपयोग:
  - मुद्रास्फीति का मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक है,
  - राष्ट्रीय सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा में रखने और मूल्य स्थिरता की निगरानी के साधन के रूप में उपयोग,
  - राष्ट्रीय खातों में अवस्फीतिकारक (Deflators) के रूप में,
  - कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए।
- CPI का आधार वर्ष 2012 कर दिया गया है।



### राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के ज़रिए 71 महत्वपूर्ण दवाइयों के मूल्य तय किए हैं।

NPPA के बारे में

- स्थापना: 1997 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग (DoP) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापना की गई।
- उद्देश्य:
  - दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र विनियामक के रूप में कार्य करना, और
  - वहनीय कीमतों पर दवाइयों की उपलब्धता और सुलभता सुनिश्चित करना।
- कार्य: औषध विभाग द्वारा जारी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) के तहत दवाइयों की कीमत तय करना और समय-समय पर उनमें बदलाव करना।



### बेदीनखलम उत्सव (Behdeinkhlam festival)

हाल ही में, मेघालय में पवित्र बेदीनखलम उत्सव मनाया गया।

‘बेदीनखलम उत्सव’ के बारे में

- इस उत्सव का शाब्दिक अर्थ है “महामारी को दूर भगाना”। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण और समुदाय द्वारा चुनौतियों से निपटने की क्षमता का प्रतीक है।
- यह पनार (या जयंतिया) जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य-उत्सव है। इसे हर साल जुलाई में फसल बुवाई के बाद मनाया जाता है।
- उत्सव के दौरान, युवा पुरुष बांस के डंडों से प्रत्येक घर की छत पर प्रहार करते हैं। यह बुरी आत्माओं, महामारी और बीमारियों को दूर भगाने का प्रतीक है।
- इस दौरान दैत-लावाकोर (लकड़ी की गेंद से खेला जाने वाला फुटबॉल जैसा खेल) और इयातान-भांग (रस्साकशी) जैसे खेल खेले जाते हैं।



### रैम एयर टर्बाइन (RAT)

अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में रैम एयर टर्बाइन (RAT) की सक्रियता का उल्लेख किया गया है।

‘रैम एयर टर्बाइन (RAT)’ क्या है?

- यह एक छोटा टर्बाइन होता है जिसे आमतौर पर विमान के फ्यूजलेज या विंग के एक कम्पार्टमेंट में लगाया जाता है।
- कार्य: इसका मुख्य कार्य विमान की मुख्य प्रणाली विफल होने पर आपातकालीन शक्ति (ऊर्जा) प्रदान करना है।
- यह विमान की गति के आधार पर वायु की गति से शक्ति उत्पन्न करता है। यह एक विद्युत जनरेटर या एक हाइड्रोलिक पंप से जुड़ा होता है।
- विमान की ईंधन आपूर्ति बाधित होने पर यह सिस्टम मैनुअल रूप से या स्वतः कार्य करने लगता है।



### क्वांटम नॉइज़

एक नए अध्ययन के अनुसार क्वांटम नॉइज़ कभी-कभी क्वांटम एंटेगलमेंट को उत्पन्न या पुनर्जीवित कर सकता है।

क्वांटम नॉइज़ क्या है?

- क्वांटम नॉइज़ उन अवांछित व्यवधानों को कहा जाता है जो क्वांटम प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, जिससे क्वांटम गणनाओं में त्रुटियाँ आती हैं।
- परंपरागत रूप से, क्वांटम नॉइज़ को एंटेगल सिस्टम का शत्रु माना जाता है, क्योंकि इससे वे अपना एंटेगलमेंट खो देते हैं। इस परिघटना को ‘डीकोहेरेंस’ नाम से जाना जाता है।
- क्वांटम एंटेगलमेंट एक रहस्यमय संबंध है जो एक ही स्रोत से उत्पन्न अलग-अलग कण समय और दूरी के मामले में अलग होने पर भी आपस में जुड़े होते हैं।



### शिकानसेन तकनीक (Shinkansen Technology)

नेक्स्ट जनरेशन E10 शिकानसेन ट्रेनें भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाएंगी। भारत में ये रेलगाड़ियां मुंबई-अहमदाबाद के बीच बन रहे 508 किलोमीटर के हाई स्पीड यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच चलेंगी।

शिकानसेन तकनीक के बारे में

- शिकानसेन जापान की हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन है।
- यह विश्व की सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद, उच्च गति, उच्च क्षमता और हाई फ्रीक्वेंसी वाली परिवहन प्रणाली मानी जाती है।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - यह टक्कर-रोधी (Crash Avoidance) सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे दो प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है:
    - ◆ हाई-स्पीड रेल के लिए विशेष ट्रैक, जो लेवल क्रॉसिंग (समपार) रहित होते हैं।
    - ◆ ATC सिस्टम (ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम), जो ट्रेन की गति को नियंत्रित करके किसी भी टक्कर को रोकता है।
  - इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: ट्रेन के आगे के हिस्से का एयरोडायनामिक डिज़ाइन, वाहन से उत्पन्न शोर में कमी, ऊर्जा बचाने वाली ट्रेक्शन प्रणाली और आरामदायक सफर।

## सुर्खियों में रहे स्थल



### ऑस्ट्रेलिया (राजधानी: कैनबरा)

ऑस्ट्रेलिया और भारत “मैत्री ग्रांट्स 2025” के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

- ‘मैत्री ग्रांट्स’ सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया-इंडिया रिलेशन्स’ द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य संस्कृति, शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ाना है।

भौगोलिक अवस्थिति:

- स्थिति: ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है।
- समुद्री सीमा: इसके पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर है।
- ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है।

भौगोलिक विशेषताएं

- उच्चतम बिंदु: माउंट कोसियस्ज़को। यह पूर्वी हाइलैंड्स/ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है।
- द ग्रेट बैरियर रीफ: यह क्वींसलैंड प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति (कोरल रीफ) समूह है। इसे 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था।
- प्राप्त प्रमुख संसाधन: स्वर्ण, लौह अयस्क, सीसा, निकल, रूटाइल, यूरेनियम, जस्ता और जिंक्रोन।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर